



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 29, 2008/फाल्गुन 10, 1929

No. 76]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 29, 2008/PHALGUNA 10, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2008

जांच शुरुआत

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : ईरान इस्लामिक गणराज्य के मूल के या वहां से निर्यातित हेक्सामेथिलिन टेट्रामाइन (हेक्सामाइन) के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच से संबंधित निर्णायक समीक्षा की शुरुआत।

सं. 15/10/2007-डीजीएडी.—यतः वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 23 दिसम्बर, 2002 की अधिसूचना द्वारा अन्तिम शुल्क की सिफारिश की थी और 17 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 42/2003 के तहत भारत सरकार द्वारा अन्तिम शुल्क लगाया गया था। प्राधिकारी ने ईरान के मूल के या वहां से निर्यातित हेक्सामेथिलिन टेट्रामाइन (हेक्सामाइन) (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए अंतिम जांच परिणाम जारी किए थे। दिनांक 17 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना द्वारा ईरान की मै. सिना केमिकल इंडस्ट्रीज कं. (एससीआईसी) द्वारा स्वैच्छिक कीमत वचनपत्र प्रस्तुत करने पर जांच स्थगित कर दी गई थी। तथापि, प्राधिकारी ने 15 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना द्वारा जांच पुनः शुरू की और 11 अप्रैल, 2005 की अधिसूचना द्वारा निश्चयात्मक

पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की। भारत सरकार द्वारा 30-6-2005 की अधिसूचना सं. 58/2005 के तहत निश्चयात्मक शुल्क लगाया गया था।

2. समीक्षा एवं जांच शुरुआत हेतु अनुरोध

और यतः सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 के अनुसार लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, यदि उसे पूर्व में समाप्त न किया गया हो, तो शुल्क को इस प्रकार से लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि बीत जाने पर समाप्त हो जाता है। वशतः समीक्षा में यदि केन्द्र सरकार की यह राय हो कि इस प्रकार के शुल्क को समाप्त किए जाने से पाटन एवं क्षति जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो वह इस प्रकार से लगाए गए शुल्क की अवधि को समय-समय पर आगे और 5 वर्ष की अवधि तक बढ़ा सकती है।

उपयुक्त प्रावधानों के अनुसार मै. सिमालिन केमिकल इंडस्ट्रीज और मै. कनोरिया केमिकल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि. ने ऐसी समीक्षा का अनुरोध करते हुए एक याचिका के साथ प्राधिकारी से संपर्क किया है। रिट याचिका सं. 2006 की 16893 (इंडियन मेटल एंड फैरो एलायज लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी) में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय, जिसमें यह अवधारित किया गया है कि निर्णायक समीक्षा अनिवार्य है और ऐसी समीक्षा नियमावली के नियम 23 के अनुसार की जानी अपेक्षित है, को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात की जांच करने के लिए कि क्या लागू शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी या उसकी पुनरावृत्ति होगी, अधिनियम की धारा 9(5) के अनुसार एतद्वारा निर्णायक समीक्षा की कार्यवाही शुरू करते हैं।

3. विचाराधीन उत्पाद

मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद हेक्सामेथिलिन टेट्रामाइन था जिसे बाजारी भाषा में हेक्सामाइन भी कहा जाता है। हेक्सामेथिलिन

टेड्रामाइन मीठा धात्विक स्वाद वाला सफेद रखादार पाउडर है। अपने शुद्ध रूप में यह रंगहीन और गंधहीन है। यह रोम्बिक डोडेकाहेड्रन्स में क्रिस्टलीकरण करता है। हेक्सामेथिलिन टेड्रामाइन योगिक को एमोफॉम, मिथेनामाइन, सिस्टामाइन, सिस्टोजन, यूरोट्रोपिन के नाम से भी जाना जाता है। यह सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 और आईटीसी सं. 2921.2901 के अंतर्गत वर्गीकृत है। हेक्सामाइन का सर्वाधिक प्रमुख औद्योगिक उपयोग ठोस फेनॉलिक रेजिनों के विनिर्माण हेतु किया जाता है। इसका एक अन्य महत्वपूर्ण उपयोग अत्यधिक विस्फोटक साइक्लोनि के विनिर्माण हेतु किया जाता है। कार्य में बैक्टीरिया रोधी होने के कारण हेक्सामाइन का उपयोग यूरीनरी एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। यह उस उत्पाद की निर्णायक समीक्षा है जिस पर पहले से ही शुल्क लागू है। अतः विचाराधीन उत्पाद अपरिवर्तित रहेगा।

4. प्रक्रिया

इस जांच में इस बात का निर्धारण किया जाएगा कि क्या लागू शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

(i) इस समीक्षा में दिनांक 11-4-2005 की अधिसूचना सं. 14/35/2002-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल होंगे;

(ii) इस जांच में शालिम देश ईरान है;

(iii) वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1-1-2007 से 31-12-2007 तक की है।

(iv) इस जांच में उपर्युक्त नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

5. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देश के निर्यातकों, भारत में उसके दूतावास के जरिए ईरान इस्लामिक गणराज्य की सरकार, भारत में उक्त उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए और निम्नलिखित को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,

वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी जांच से संगत अपने अनुरोध नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से प्रस्तुत कर सकती है।

4.2 समय सीमा

वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध लिखित में भेजा जाए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40

दिन) से पूर्व पहुंच जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त हुई सूचना अधूरी है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

4.3 अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई किसी भी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सार प्रस्तुत करना अपेक्षित है। अन्य हितबद्ध पार्टियों को सूचना की सार्थक समझ प्रदान करने के लिए गोपनीय सूचना के अगोपनीय रूपांतरण या उसके अगोपनीय सारांश में पर्याप्त व्यौरा दिया जाना चाहिए। यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाली पार्टी की राय में ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव न हो तो उसके कारण का एक विवरण उपलब्ध कराना अपेक्षित होता है।

4.4 उपलब्ध तथ्यों का उपयोग

यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

4.5 सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश रखे हुए हैं।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th February, 2008

Initiation

(Sunset Review)

Subject : Initiation of Sunset Review anti-dumping investigation concerning imports of Hexa Methylene Tetramine (Hexamine) originating in or exported from the Islamic republic of Iran

No.15/10/2007-DGAD.—Whereas the Designated Authority, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, recommended imposition of provisional duty *vide* notification dated 23rd December, 2002 and provisional duty was imposed by the Govt. of India, *vide* notification No. 42/2003 dated 17th March, 2003. The Authority issued its Final Findings recommending imposition of definitive Anti-Dumping Duty on Imports of Hexa Methylene Tetramine (Hexamine) (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from Iran. *Vide* notification

dated 17th September, 2003 the investigation was suspended upon voluntary price undertaking by M/s. Sina Chemical Industries Co. (SCIC) of Iran. However, the Authority resumed the investigation vide notification dated 15th October, 2004 and recommended definitive anti-dumping duty vide notification dated 11th April, 2005. Definitive duty was imposed by the Govt. of India vide Notification No. 58/2005, dated 30-06-2005.

2. Request for Review and Initiation

And whereas in terms of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 the anti-dumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition. Provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may from time to time extend the period of such imposition for a further period of five years. In terms of the above provisions, M/s. Simalin Chemical Industries and M/s. Kanoria Chemicals and Industries Limited have approached the authority with a petition requesting for such a review. In view of the judgment of the Hon'ble Delhi High Court in the Writ Petition No. 16893 of 2006 (Indian Metal & Ferro Alloys Ltd. Vs. Designated Authority) holding that sunset review is mandatory and such review is required to be carried out in terms of Rule 23 of the Rules, the Designated Authority hereby initiates the sunset review proceedings, in accordance with Section 9A(5) of the Act, to examine whether cessation of the duty in force would lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

3. Product under consideration

The product under consideration in the original investigation was Hexa Methylene Tetramine, also known as Hexamine in market parlance. Hexa Methylene Tetramine is a white crystalline powder with a sweet metallic taste. In the pure form, it is colourless and odourless. It crystallizes in rhombic dodecahedrons. Hexa Methylene Tetramine compound is also known as Ammoform, Methenamine, Cystamine, Cystogen, Urotropine. It is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 and ITC No. 2921.2901. Most important industrial use of Hexamine is for the manufacture of solid phenolic resins. The other important use is for the manufacture of a high explosive cyclonic. Hexamine being anti-bacterial in action is used as a urinary antiseptic. This being a sunset review of the product against which duty is already in force the product under consideration shall remain unchanged.

4. Procedure

The investigation will determine whether the cessation of the duty in force is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

- (i) The review will cover all aspects of Notification No. 14/35/2002-DGAD, dated 11-4-2005;
- (ii) The country involved in this investigation is Iran;
- (iii) The period of investigation for the purpose of the present review is from 1-1-2007 to 31-12-2007;

- (iv) The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rule supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

4.1 Submission of Information :

The exporters in subject country, the Government of Islamic Republic of Iran through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product and the domestic industry, are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority in the following address :

The Designated Authority

Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Government of India

Ministry of Commerce and Industry

Department of Commerce

Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

4.2 Time Limit :

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

4.3 Submission of information on Non-confidential basis :

In terms of Rule 6(7), of the Rules the interested parties are required to submit non-confidential version of any confidential information provided to the Authority. The non-confidential version or non-confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties. If in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summary, a statement of reason thereof is required to be provided.

4.4 Use of facts available :

In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

4.5 Inspection of public file :

Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties in terms of Rule 6(7).

R. GOPALAN, Designated Authority